certain unlawful activities of individuals and associations and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Further debate on this will continue tomorrow. we will go to the next item now.

DISCUSSION RE: ILLEGAL OCCUPATION OF INDIAN TERRITORY BY CHINA, PAKISTAN AND OTHER COUNTRIES AND STATEMENT ON AREA OF INDIA BY MINISTER OF EDUCATION

Mr. Speaker: Mr. Kanwar Lal Gupta.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I have a submission to make.

श्री यशपाल सिंह (देहरादून : मेरा रेजोल्युशन इस के साथ है । सब से पहले मेरा रेजोल्युशन है । पैरलल रेजोल्युशन चल रहा है । आई में बी गिवैन ए चांस . . .

Mr. Speaker: I do not have it in the agenda paper.

श्री यशपाल सिंह : मेरा जो रेजोल्यशन चल रहा है उस का क्या हुआ ? सरकारी सूची में मेरा रेजोल्युशन है, पैरलल रेजोल्युशन है. . .

Mr. Speaker: I do not know where it is. At least it is not in today's agenda.

श्री मधु लिमये : मैं आप का ध्यान निर्देश संख्या 115 की ओर खींचना चाहता हूं । मैं बहस का विरोध नहीं कर रहा हूं ।

Mr. Speaker: Let us see tomorrow. Of course, I do not assure, I am not sure, that it will come tomorrow. I can say that it is not there in today's agenda.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, निर्देश 115 के माननीय इनकरैक्ट स्टैटमैंट्स मेड इन दी हाउस इत्र को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है उस के सम्बन्ध में यह 17 जुलाई को लाठीटीला, डूमाबाड़ी के बारे में एक लम्बा बयान दिया था । वह करीब करीब 5 सफे का है और पिछले तीन, चार साल में जो भी यहां पर कहा गया है उस की खोज करके मैं ने यह बयान दिया था, तो मंत्री महोदय के द्वारा जो गलत बयानी की गई है उस को शुद्ध करने का आप कोई रास्ता निकालिये । मैं अपना बयान अभी रखता हूं या कल इस को रखिये । अब यह पांच, पांच सफे का इतनी मेहनत करने के बाद मैं बना पाया हूं, वह 17 जुलाई को बयान दिया है । तो इस बहस के बाद क्या मुझे आप उसे रखने की इजाजत देंगे ?

Mr. Speaker: He can give it. It may be considered. This will also come. He may himself correct.

Shri S. M. Banerjee: When Mr. Chagla was replying to the call-attention motion regarding Latithilla and Dumabari, he made certain statements.....

Mr. Speaker: No, no. I will not allow. He is making a speech.

Mr. Kanwar Lal Gupta.

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर ऐतराज करता हूं कि जब किसी का मोशन आने को होता है और वह बुला लिया जाता है तो बीच में इस तरह से दूसरे मैम्बर्स खड़े होकर दखल देने लगते हैं तो यह कोई उचित बात नहीं है ।

Shri S. M. Banerjee: Your office wrote to us . . . (*Interruptions*).

Mr. Speaker: That has nothing to do with this.

Shri S. M. Banerjee: Are you following any rule or not? I was made a fool in writing a letter for nothing. Why should I write a letter? We

[Shri S. M. Banerjee]

actually submit something, but we get something from the office saying, "Do not move it as call-attention, do not move it as an adjournment motion, move under 115 of the 'Directions by the Speaker'. That has been rotting for 15 or 20 days . . .(*Interruptions*) Then I will not take your note seriously.

Mr. Speaker: I will be very happy if he does not take it seriously. Will he kindly sit down? He is indulging in irrelevant talks.

Shri S. M. Banerjee: What is irrelevant? There is nothing irrelevant. You read your record.

Mr. Speaker: Mr. Kanwar Lal Gupta may start.

श्री कँवरलाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, इस बीस साल में हमारे देश की जो सीमाएं हैं उन के ऊपर चीन, पाकिस्तान ने एक बार नहीं अनेक बार आक्रमण किया है पहला सवाल अध्यक्ष महोदय, मैं यह उठाता हूं कि हमारे देश की सीमाएं हैं या वास्तव में हमारी सीमाओं का वर्णन हमारे संविधान के पहले शैड्यूल में पहले हिस्से में किया हुआ है। उस के अन्दर स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि उन प्रान्तों की यूनियन टरीटैरीज की जो सीमाएं हैं वह उस में बताई गई हैं। उस के साथ साथ अध्यक्ष महोदय, हमारे देश का ऐरिया कितना है इस के बारे में भी इस सदन् में कई बार सवाल उठे हैं। अभी जो यू० एन० स्टैटिस्टिकल आफिस के पबलिकेशन ने जो आंकड़े दिये हैं, 1957 के उस के हिसाब से हमारे देश का ऐरिया 32 लाख 88 हजार 876 स्कवायर किलोमीटर है, और 1964 में उसी यू० एन० स्टैटिस्टिकल आफिस पबलिकेशन ने जो आंकड़े दिये उसके अन्दर हमारे देश का जो ऐरिया है वह 30 लाख 66 हजार 232 स्कवायर किलोमीटर रह गया। इस का मतलब यह है कि 7 लाख में से 2 लाख, 42 हजार, 642 वर्ग किलोमीटर एरिया हमारे देश का कट गया। शायद इन आंकड़ों में जम्मू और काश्मीर का हिस्सा शामिल नहीं है। सरकार द्वारा जो किताब हमें दी जाती है उस में भी और जो "इंडिया" नाम का एक पब्लिकेशन निकलता है उस में भी, कई तरह के आंकड़े हैं। सरकारी एजेन्सी के जरिये जो भी आंकड़े दिये जाते हैं, अगर वह मिलाये जायें तो वह मिलते नहीं। इस का जवाब 1966 के अन्दर सरकार की तरफ से यह दिया गया कि यहां पर कई लिंग्विस्टिक डिवीजन हो गये, इस की वजह से कुछ एरिया कम और ज्यादा होता है। नई सर्वे होती रहती है उस की वजह से भी कुछ एरिया कम ज्यादा होती रहती है। सरकार का यह आर्गूमेंट कन्विंसिंग नहीं क्योंकि अगर आप ठीक तरह से सर्वे करते हैं तो आप को मालूम होना चाहिये कि हमारे देश का एरिया कितना है। दुनिया में हो सकता है कि दो देश ऐसे हों जिन का एरिया बदलता रहता हो, लेकिन अधिकांश देश ऐसे हैं जिन का एरिया निश्चित है। वह आज भी वही होगा, कल भी उतना ही होगा और दस वर्ष बाद भी उतना ही होगा।

1966 में मंत्री महोदय ने यह कहा था कि अब हम एक नई मशीनरी डेवेलप करेंगे और सारे सर्वे के काम को अपने हाथ में लेंगे। उस को इम्प्रूव कर के देश की जो निश्चित एरिया बैठती है वह हम बतलायेंगे। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस एक या डेढ़ साल के अन्दर उन्होंने इस मामले में कौन सी कार्रवाई की। हमारे देश की एरिया कितनी है यह निश्चित होना चाहिये ; और उस की फिजिकल बाउंड्री निश्चित होनी चाहिये। आज यह काम कठिन होगा, यह मैं मानता हूं, लेकिन भले ही वह कठिन हो पर वह कठिन काम होना चाहिये। हमें यह मालूम होना चाहिये कि हमारे देश की कितनी एरिया है और

यह उस की फिजिकल बाउंड्री है। आज बीस साल के बाद भी यह एरिया बदलती रहती है और इस में काफी वैरिएशन होता रहता है। इस समय ढाई लाख वर्ग किलो-मीटर का वैरिएशन हे, यह चीज बिल्कुल भी मेरी समझ में नहीं आती।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे देश की टैरिटरी है, जो भी सीमायें हमारे देश की हैं, उस में हमारी सरकार की पहली जिम्मेदारी है, उस की लीगल, मारल और कांस्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी है, कोई भी सरकार हो, वह देश के फ्रंटिअर्स की रक्षा करे। लेकिन, मैं कहना चाहता हूं, सरकार उस जिम्मेदारी को पूरा करने में पूरी तरह नाकामयाब हुई है। बार बार यह कहने के बाद भी कि हम एक इंच जमीन भी नहीं देंगे, 1950 में हमारे माननीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम किसी को मैकमोहन लाइन पर नही जाने देंगे, उस के बाद एक बार नहीं, मैं पिछले दो सालों की प्रोसीडिंग्स पढ़ रहा था, एक साल के अन्दर मिनिस्टर ने सरकार की तरफ से 23 बार यह घोषणा की कि हम एक इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। लेकिन वह फूट कितना लम्बा है, मालूम नहीं। वह इंच कितने के बराबर है यह मालूम नहीं। आज 50 हजार वर्ग मील हमारे देश का पाकिस्तान के पास है और चीन के पास है, लेकिन सरकार का एक इंच अभी तक पूरा नहीं हुआ।

श्री जी० आ० कृपालानी : (गुना) : वह इंच ब्रह्मा का है।

श्री कंवरलाल गुप्त : श्री कृपालानी कहते हैं कि वह इंच ब्रह्मा का है। वह लम्बा होता जाता है। कितना लम्बा होगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन यह जो जवाब हैं कि सूटेबल मेजर्स लिये जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोई जमीन नहीं देंगे, यह सब थोथी बातें हैं। सरकार की जो डिफेन्स पालिसी है, वह इमैंजिनरी है, अनरिअलिस्टिक है और उस के अन्दर बुजदिली छिपी हुई है।

जब कभी कोई स्टैन्ड लेने की बात आती है, तो उस समय हमारी सरकार पीछें भागती है कि किसी न किसी तरह से एडजेस्टमेंट कर लो। लड़ाई अवायेड करो। यह सरकार कम्प्रोमाइज की सरकार है, ऐडजस्टमेंट की सरकार है। इस सरकार को स्टैन्ड लेना बिल्कुल नहीं आता। यह स्टैन्ड लेने से डरती है। लड़ाई कोई भी नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता। कोई समझदार आदमी लड़ाई नहीं चाहता। लड़ाई के कितने खतरनाक नतीजे होते हैं, हम जानते हैं। लेकिन अगर सामने धोंखेबाज दुश्मन हो और वह लड़ाई चाहता हो और आप पर आक्रमण करता है, लेकिन आप भागते हैं तो इस से लड़ाई टलने वाली नहीं है। लड़ाई और नजदीक आयेगी। लेकिन उस के मुकाबले में अगर हम लड़ाई की तैयारी करते हैं, यह सोच कर के कि हम को किसी पर भी आक्रमण नहीं करना है, भारत कभी भी एक्सपैन्शनिज्म पर विश्वास नहीं करता, भारत की संस्कृति इस प्रकार की नहीं है, पर अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो उस का जवाब हम जरूर देंगे, तो हमारी स्थिति कभी भी खराब नहीं हो सकती। अगर यह नीति सरकार पहले अपना लेती तो हमारी आज जो स्थिति है वह न होती।

आप को यह जान कर ताज्जुब होगा कि चीन द्वारा 18 जुलाई, 1967 तक 88 बार बार्डर वायोलेशन हुए और ताशकन्द ऐग्रीमेंट के बाद आज तक जम्मू और काश्मीर बार्डर के ऊपर पाकिस्तान द्वारा 2,082 बार्डर वायोलेशनस हुए। इस समय हमारी 50,000 वर्ग मील जमीन दुश्मन के कब्जे में है। 2,082 बार्डर वायोलेशन्स हुए हैं।

[श्री कंवरलाल गुप्त]

जब कि हम ने ताशकन्द ऐग्रीमेंट किया हुआ है। चीन ने कितनी ही बार बार्डर वायोलेशन किये हैं, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि हम एक इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। हम मजबूती से खड़े हैं। आज दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिस के ऊपर पिछले बीस सालों में उतनी बार आक्रमण हुए हों जितनी बार भारत के फ्रंटिअर्स के ऊपर, हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुए हैं। इस के मतलब यह हैं कि जो हमारी सरकार की पालिसी है, चाहे एक्स्टर्नल अफेअर्स की पालिसी हो, चाहे डिफेन्स की पालिसी हो, वह दोनों मिले जुले हैं, वह हमारी सरकार के दिवालियेपन का सबूत हैं।

I should get 20 minutes.

Mr. Speaker: Within half an hour? How will others speak? Ten minutes normally.

Shri Kanwar Lal Gupta: This debate is going to continue for two hours.

Mr. Speaker: Don't waste time in between. Others also must speak. I am worried about that.

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरी सरकार से यह मांग है कि वह ताशकन्द समझौते वाली जो चीज है उसको खत्म करे। उससे कोई फायदा नहीं है। उसको दुनिया को यह बतला देना चाहिये कि पाकिस्तान हो या चाइना हो, जो जमीन उसके पास हमारी है उसको वह छोड़ें। हम उनके साथ दुश्मनी नहीं चाहते, वह तरक्की करें, हम को कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर हिन्दुस्तान की एक इंच जमीन भी रख कर वह बात करेंगे तो हम उन से बात करने के लिये तैयार नहीं। जो दुश्मन है वह दुश्मन है, जो दोस्त है वह दोस्त है। लेकिन हमारी जो सरकार है उसका कोई दोस्त भी नहीं और कोई दुश्मन भी नहीं क्योंकि न वह किसी के साथ दोस्ती करना जानती है और न दुश्मनी करना जानती है। जो दुश्मन हमारी जमीन में छिपे बैठ हैं, उनके साथ किस तरह का बरताव करना चाहिये यह सरकार नहीं जानती है।

एक चीज के बारे में मुझे सख्त एतराज है, और वह यह कि एक तो हमारे देश में बीस साल पहले सरदार पटेल हुए, जिन्होंने हमारे देश की बाउंड्री को आगे बढ़ाया, लेकिन उनके मरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह बाउंड्री सिकुड़ती जा रही है। मैं इस सरकार के ऊपर चार्ज लगाना चाहता हूं, एलिगेशन लगाना चाहता हूं, कि उसने हमारे देश का जो हिस्सा था वह पाकिस्तान को दिया कई बाउंड्रीज के ऊपर, लेकिन उस ने न तो उसके बारे में लोक सभा को बतलाया और न देश को बतलाया। कभी उसकी चर्चा तक नहीं की। यह एक ब्रीच आफ ट्रस्ट है, वायोलेशन आफ दि कांस्टिट्यूशन है। यहां जो शपथ आप ने ली है यह उसके विरुद्ध है, आप ने अपने देश के साथ धोखा किया है, इस लोक सभा के साथ धोखा किया है।

मैं आप के सामने बतलाना चाहता हूं कि एक सवाल मैं ने पूछा था मंत्री महोदय से 31 जुलाई, 1967 को। मैंने एक सवाल किया था कि कब से और कौन कौन से इलाके पाकिस्तान के पास हैं। इसके जवाब में मुझे बताया गया कि बासुमारी मधुबनी यह 1947 से है, बेरुबाड़ी 1947 से है। इसके अलावा रंगपुर सैक्टर में 1956 से पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। यह जो टी एस्टेट युनाइटेड खासी हिल्स के अन्दर है वहां 1962 में पाकिस्तान ने कब्जा किया था। इसके अलावा सुरमा रिवर के ऊपर 1962 में कब्जा किया है। नवगांव के अन्दर 1961 में कब्जा किया और पालाटौल टी एस्टेट के अन्दर जो सिलहट के पास है 1961 में कब्जा

किया । भागलपुर गांव के ऊपर 1964 में कब्जा किया । लाठीटीला के बारे में एक सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा था कि 748 बीघा जमीन पर पाकिस्तान ने 1962 में कब्जा कर लिया था । मैं लम्बी कहानी कहना नहीं चाहता हूं । लेकिन आप देखें कि दो मिलिटरी आफिसर्स ने मिल कर फरवरी, 1966 में पाकिस्तान से यह एग्रीमेंट कर लिया है कि 748 बीघा जमीन जो है वह पाकिस्तान को दे दी जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि इस एग्रीमेंट को करने का उनको क्या अख्त्यार था ?

इसी प्रकार से जो एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है, कोई 1962 से है और कोई 1964 से है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आप ने कब लोक सभा को जानकारी दी, कब व्हाइट पेपर निकाला, कब कोई स्टेटमेंट दिया और कब मैम्बरों ने सवाल पूछे और कब आपने उनके उन सवालों का जवाब दिया । इस सरकार को देश की एक इंच भूमि भी किसी को देने का हक़ हासिल नहीं है फिर चाहे मिलिटरी कमांडर्ज़ इसको तय करें या मिनिस्टर तय करें । जो कुछ भी करना है वह पहले से लोक सभा के सामने आना चाहिये । यहां पर बात तय होनी चाहिये । उस चीज़ को पहले से देश के सामने लाया जाना चाहिये । इस प्रकार की कार्रवाई दुनिया की शायद किसी भी सरकार ने न की होगी जिस प्रकार की आप ने की है । देश के हिस्सों को आहिस्ता आहिस्ता तश्तरी में रख कर आप दूसरों को देते जा रहे हैं लेकिन जनता को उसके बारे में बताते तक नहीं हैं, लोक सभा को बताते तक नहीं हैं । मैं समझता हूं कि जानबूझ कर नहीं बताया जाता है, ये लोगों से डर रहे हैं । अगर ये हमें बतायें तो नंगे हो जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से सरकमस्टांजिस थे जिन में ये एरियाज़ पाकिस्तान के कब्जे में जाने दिये और आपने क्या कार्रवाई की और आप ने लोक सभा को और देश को क्यों नहीं इसके बारे में बताया । मेरा यह चार्ज है कि आप ने जानबूझ कर नहीं बताया । यह देश के साथ वफादारी नहीं है । मुझे कहना पड़ेगा गो मैं कहना नहीं चाहता था कि यह देश के साथ गद्दारी है । अगर मंत्री महोदय और यह सरकार ज़रा भी जिम्मेदारी से काम करना चाहती है तो इसको चाहिये कि यह लोक सभा के सदस्यों की एक कमेटी बनाये और उस कमेटी की टर्म्ज़ आफ रेफ्रेंस में यह हो कि आज तक जो भी समझौते आपने किये हैं, उनको वह देखे, वे सब समझौते उस कमेटी के सामने आयें और वह कमेटी इस बात का पता लगाये कि कब से और कौन सा इलाका हमारे देश का दूसरे किसी देश के पास गया और आया उसके बारे में लोक सभा को बताया गया या नहीं बताया गया और बताया गया तो कब बताया गया । वह यह भी तय करे कि आपको कोई कांस्टिट्यूशनल राइट था या नहीं था किसी इलाके को इस तरह से दे देने का ।

मैंने सुना है कि जब कच्छ का समझौता इंग्लैंड में हुआ था उस समय कुछ नक्शा बनाया गया था । उस नक्शे के अन्दर कुछ हिस्से पर पाकिस्तान को पैट्रोलिंग करने का हक़ दे दिया गया था । वह नक्शा आज तक आपने हमारे सामने नहीं रखा है । किसी को आपने उसके बारे में नहीं बताया । कोई भी चीज़ आप इस तरह की करते हैं और देश को नहीं बताते हैं तो मैं समझता हूं कि जो शपथ आपने खाई है उसके विपरीत आप जाते हैं और यह एक ब्रीच आफ ट्रस्ट है ।

अब सवाल यह रह जाता है कि पचास हज़ार मील भूमि को किस तरह से वापिस लिया जाना चाहिये । आप लड़ाई ही लड़ कर लें यह मैं नहीं कहता हूं । लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि पोलिटिकल, डिप्लोमैटिक आदि सब प्रकार के प्रेशर चीन और पाकितान पर आपको डालने चाहिये । मैंने अभी आपको कहा है कि आप दुश्मन को दुश्मन नहीं मानते हैं । तब आप

[श्री कंवरलाल गुप्त]

कैसे कोई पोलिटिकल प्रेशर चीन पर ला सकते हैं। यहां पर दलाई लामा बैठे हुए हैं। तिब्बत के बारे में जो शर्तें चीन ने हमारे साथ की थीं उनको चीन ने पूरी तरह नहीं निभाया है, सारी शर्तों को पूरा नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आप दलाई लामा की सरकार प्रदान करें और आप कहें कि तिब्बत में दलाई लामा की सरकार है और तिब्बत के ऊपर कोई हक़ नहीं है। जब चीन पूरी तरह से शर्तों को नहीं मानता है तो आप क्यों मानें।

मैं यह भी मांग करता हूं कि आप चीन के साथ अपने डिप्लोमैटिक रिलेशन्ज़ तोड़ दें। जब दुश्मन आपकी साढ़े चौदह हज़ार मील भूमि पर कब्ज़ा किये बैठा हो और आप झांकी देखना चाहते हों पेकिंग में बैठ कर तो मैं कहूंगा कि वह हवा आपके गले को दबा देगी। वहां बैठ कर आप ठंडी हवा नहीं ले सकते हैं। दुनिया को पता होना चाहिये कि चीन के साथ आपकी दुश्मनी है। लेकिन आप तो उसके साथ दोस्ती की पेंगें बढ़ा रहे हैं और दुनिया को कहते हैं कि यह हमारा दुश्मन है। इस तरह की बात नहीं चल सकती है।

यू० एन० ओ० में आपको चीन की वकालत करना बन्द कर देना चाहिये। ताइवान गवर्नमेंट से आपके डिप्लोमैटिक रिलेशन्स होने चाहियें। जब तक चारों ओर से चीन पर दबाव नहीं पड़ेगा, डिप्लोमैटिक, पोलिटिकल आदि तब तक चीन की अकल ठिकाने नहीं आयेगी।

इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि खान अब्दुल गफ्फार खां को आप यहां बुलायें, और खुले आम एलान करें कि हम पख्तूनिस्तान की हिमायत करेंगे और हम आपकी हिमायत करते हैं। इस तरह से आप चीन और पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। जब वह मिजोज़ को, नागाज़ को भड़काता है और इनफिलट्रेटर्ज़ को भेजता है और हमारे फंटियर्ज में गड़बड़ करवाता है और चीन और पाकिस्तान दोनों नागाज़ को, मिजोज़ को हथियार देते हैं, हमारे इंटरनल मैटर्ज़ में इंटरफीअर करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट को भी उसका वैसा ही बदला देना चाहिये। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

आपको केवल कनवैंशनल आर्म्ज पर ही भरोसा नहीं करना चाहिये। इससे बात नहीं चलेगी। आपको एटम बम बनाना होगा। आपके ऊपर अमरीका का, रूस का, चीन का, पाकिस्तान आदि का दबाव है, वे आप पर दबाव डाल रहे हैं। अगर आपने एटम बम बना लिया तो वह दबाव आहिस्ता आहिस्ता हट जायगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि चाहे जितना खर्च आप करें, चाहे कुछ भी करें आपको यह शपथ लेनी चाहिये कि आप जितना भी पैसा डिफेंस के लिये चाहिये देंगे। इसके लिये आपको कमर कस कर चलना होगा। हमें सोफिस्किेटिड आर्म्ज रखने चाहियें। हमारे पास नाइट फाइटर्ज होने चाहियें। और भी जो हथियार हमें चाहियें वे हमारे पास होने चाहियें। जब तक हमारी बाहर की नीति ठीक नहीं होगी तब तक कितना भी पैसा आप लगायें, काम नहीं चलेगा।

बर्मा, नेपाल, इंडोनेशिया जो आज चीन से तंग हैं, उनसे आप बातचीत करें। और यह जो कामन डेंजर है इसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है, इसको आप सोचें। मिजोलैंड, नागालैंड, असम बोर्डर, नक्सलबाड़ी, जम्मू काश्मीर का बार्डर आदि जो हमारे बोर्डर हैं ये बहुत सेंसेटिव हैं, यहां बहुत डिसटरबेंस है। कोई भी देश अपने देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता है अगर उसके सारे बोर्डर्ज इस तरह से डिसटर्ब्ड हों। मैं नहीं कहता हूं कि आप वहां गड़बड़ करने वाले लोगों को गोली से उड़ा दें। लेकिन कोई

भी आदमी को, जो हमारी फौज के ऊपर हमला करता है, जो हमारे पुलिसमैनों को मारता है और एलानिया कहता है कि हम हिन्दुस्तान में रहना नहीं चाहते हैं वह हमारा आदमी नहीं है और उसके साथ नरमी बरते जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपको याद होगा कि पिछली लड़ाई में जब प्राइम मिनिस्टर का लड़का जा कर जासूसी करता था हिटलर के कैम्प में, तो उस प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि यह मेरा लड़का नहीं है, इसे गोली से उड़ा दो, मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। जो समस्यायें नागाज की हैं, मिजोज की हैं, उनके बारे में मतभेद हो सकता है। लेकिन जो लोग देश के प्रति लायलटी नहीं रखते हैं, इस तरह के जितने भी एलीमेंट हैं उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिये और यह देखा जाना चाहिये कि जो हमारे बोर्डर्ज हैं वे शान्त रहें, वहां पर ऐसे लोग रहें जोकि भारत के प्रति लायल हों और जो पूरी तरह भारत के साथ हों।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय में हिम्मत है तो वह साबित करें कि उनका केस ठीक है और लोक सभा के सदस्यों की वह एक कमेटी बनायें।

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, भारत के क्षेत्रफल की बहस असल में भारत माता की बहस है और इस पर यह माननीय सदन कोई डेढ़ दो वर्ष से लगा हुआ है। असल में यह राष्ट्रीयता का मामला है और मुझसे अभी दो दिन पहले किसी ने सवाल पूछा कि राष्ट्रीयता अपने देश में कम हो रही है या बढ़ रही है? एकदम मुझको यह जवाब सूझा जो मैं समझता हूं कि सही है कि अगर अन्दरूनी ढंग से देखा जाय तो राष्ट्रीयता घट रही है और प्रादेशिकता बढ़ रही है। लेकिन अगर परदेश के प्रति देखा जाय खास तौर से चीन के प्रति देखा जाय तो राष्ट्रीयता बढ़ रही है कुछ वर्गों को छोड़ कर के उनके बारे में तो मैं ज्यादा जिम्मेदारी नहीं ले सकता। और इसी तरह से पाकिस्तान के बारे में कुछ मेरी भी और मैं समझता हूं बहुत से लोगों की मिश्रित भावना है। साधारण तौर पर हमारी इच्छा है कि यदि ऐसी स्थिति आ जाय कि जब भारत और पाकिस्तान किसी संघ में जुड़ें और फिर से हिन्दुस्तान एक हो लेकिन अगर पाकिस्तान का आक्रमण हो जाता है तो फिर उसके प्रति भी वही राष्ट्रीयता जग जाती है जो चीन के प्रति। हां, एक बात अलबत्ता सही है कि अगर कभी विश्व लोक सभा बन गई—लोक-सभा लोगों के चुनाव के द्वारा लोक सभा। मैं आज के संयुक्त राष्ट्र को नहीं कह रहा हूं। क्योंकि वह तो एक सरकारों की चुनी हुई संस्था है। विश्व लोक सभा बन गई और अगर उसने कभी ऐसे फैसले किये जो हमारे खिलाफ जाते हों, या किसी और के खिलाफ तो उसका कुछ प्रचार चाहे हो लेकिन मैं समझता हूं कि धीरे धीरे जनता उसे मानने लग जायेगी। तो अब संयुक्त राष्ट्र की तरफ जब आप देखें तो एक मजेदार चीज मालूम होती है कि 1950–52 से लेकर 1960 तक यानी करीब करीब दस वर्ष तक हमारा क्षेत्रफल 32 लाख किलोमीटर दिखाया जाता रहा है कभी 32 लाख 60 हजार कभी 32 लाख 40 हजार। और सन 1961 में 30 लाख से कुछ ज्यादा एक दम दिखाया गया। मंत्री महोदय कहेंगे कि उस वक्त उन्होंने जम्मु और काश्मीर का हिस्सा निकाल दिया। यह बात अधूरी है। पूरा सत्य नहीं है। मैं आपको पूरा सत्य बताता हूं। सन 60 में जनगणना हुई थी और उस की गिनती की जा रही थी। जिस वक्त संयुक्त राष्ट्र को रपट भेजने का समय आया उस वक्त उस की गिनती पूरी नहीं हो पायी थी और यह ऐसी निकम्मी और नालायक सरकार है कि इन्होंने अधूरी गिनती को संयुक्त राष्ट्र के पास भेज दिया। यह कहते हैं कि हम ने उस पर एक नोट लगा दिया था कि देखो अभी हमारी गिनती पूरी नहीं हो

[डा० राम मनोहर लोहिया]

पाई है हम गिनती पूरी कर लेंगे तब हमको पूरा पता चल जायेगा । तब हम भेजेंगे । वह नोट भेजा या नहीं भेजा मैं नहीं जानता । आप उन से उस वक्त की फाइल मंगा कर देख सकते हैं । लेकिन इतना बिल्कुल निश्चित है कि 1961 में उन्होंने कम आंकड़े भेजे और तब से संयुक्त राष्ट्र परिषद् ने वह आंकड़े कम दिखाने शुरू कर दिये जो मेरे हिसाब से करीब 5 लाख एकड़ पड़ता है । तो यह तो मैंने 61 वाली बात बतायी । और मैं चाहता हूं कि आप मंत्री महोदय से इसका निश्चित रूप से उत्तर दिलवाइये कि उन्होंने क्यों इतना निकम्मा काम किया कि अधूरी गणना के आंकड़ों को संयुक्त राष्ट्र के पास भेज दिया । फिर एक और तर्क यहां दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र कुछ भी कहे इस से हमें क्या मतलब ? हमारी तो अपनी जमीन है जितनी हम मानते हैं । तो कोई यह रोशनारा क्लब है या जिमखाना क्लब है कि जो मन में आये कहा जाये और किया ? यह तो एक दण्ड संस्था है । हो सकता है कि सार्वभौम न हो अभी लेकिन दण्ड संस्था के सदस्य होने के नाते हमको हमेशा अपनी बातों के बारे में बड़ा खबरदार होना चाहिए और जो बयान मंत्री महोदय ने पिछली बार रखा साल भर पहले तो उसमें एक विचित्र बात आई है । उन्होंने कहा है कि और देशों से भी ऐसी गलती होती है । यह बड़ा भ्रामक तर्क है। कई देशों के आंकड़े यहां पर हैं वक्त नहीं है इसलिए नहीं बता पाऊंगा। खाली आस्ट्रेलिया का अंक इन्होंने बताया । उसका कारण है कि आस्ट्रेलिया के कुछ ग्रीक छोड़ दिए गये थे तो वह कम बताए थे । अमेरिका के आंकड़े बिलकुल दस वर्ष तक स्थिर रहते हैं फिर एक बार जाकर 1958 में एकदम बढ़ते हैं दस एक लाख के करीब क्योंकि हवाई उसमें शामिल हो जाता है । उसी तरह से रूस के आंकड़े स्थिर रहते हैं । यह सब अंक स्थिर हैं और ऐसा भ्रामक धोखे का तर्क मंत्री महोदय को नहीं देना चाहिए और माननीय सदन को भी इस बारे में बड़ा सचेत रहना चाहिए कि मंत्री लोग किस तरह से अपनी बात को सही साबित करने के लिए इधर उधर की अनर्गल चीजें कह दिया करते हैं ।

एक चीज मुझको बड़ी अजीब लगी है जो 31 जुलाई को इसी संबंध में मन्त्री महोदय ने बयान रखा है उस में आजाद काश्मीर का कहीं जिक्र नहीं है । लांगजू का जिक्र है और उस के अलावा लद्दाख का भी जिक्र है । इन दोनों में जरा फर्क करिएगा । लांगजू के लिए कहा है कि वह ऐसा इलाका है कि जिस के बारे में भारत और चीन दोनों को सन्देह है और विवादास्पद जगह है । लेकिन लद्दाख के मामले में वह जो अकसाई चीन वाला इलाका है उस के बारे में दोनों को विवाद नहीं है। चीन कहता है कि हमारा है, भारत कहता है कि उसका है । तो लद्दाख का यहां जिक्र किया गया, उस इलाके का भी जिस के बारे में विवाद है और उस इलाके का भी जिस के बारे में विवाद नहीं है । लेकिन आजाद काश्मीर का जिक्र नहीं है । बड़ी विचित्र बात मालूम होती है । अन्दर अन्दर कुछ हो रहा है क्या अध्यक्ष महोदय ? यह 31 जुलाई का है यह बयान । और होता हो तो मुझे उस में ऐतराज नहीं होगा । यह मैं आप से कह दूं कि अगर भारत पाक का संघ बनता है, हिन्दुस्तान बनता है, तो मैं बहुत ताकत के साथ कहना चाहता हूं कि काश्मीर कहां जाता है कहां रहता है इस से मुझ को मुतलक चिन्ता नहीं है । लेकिन जब तक वह संघ नहीं बनता है, तब तक आजाद काश्मीर के इलाके की गिनती इस में नहीं की गई यह बहुत बड़ा घिनौना काम है यह मैं जरूर कह देना चाहता हूं और उसी तरह से जब से इस में उन्होंने और कई एक जगहों का जिक्र किया है, लांगजू इस सदन में कई बार कहा गया कि वह तो एक दो मील का इलाका है ।

मुझे वहां के अफसरों ने जब मैं दो तीन बार गिरफ्तार होने के बाद किसी तरह से पहुंचा था, लांगजू तो नहीं उस के आस पास बताया कि वह इलाका कम से कम दो तीन सौ मील वर्ग का है। उसी तरह से बर्मा संधि का जिक्र नहीं है। उस में कितना इलाका हमारा गया, दो हजार, तीन हजार चार हजार या कितने वर्गमील गया यह मैं पक्का नहीं जानता लेकिन गया। अच्छा इसी तरह बाराहोती का यहां जिक्र है। दो बाराहोती हैं, छोटी बाराहोती और बड़ी बाराहोती। उस में कौन सा है ? और मंत्री महोदय ने सिक्किम के बारे में जिक्र जिस ढंग से कहा है मुझे तो शक होता है कि शायद सिक्किम के आंकड़े पहले गिने जाते थे; अब नहीं गिने जाते है। बहुत सन्देह की चीज है। इतना ही नहीं आप समझ कर रखिए अध्यक्ष महोदय, कि सर्वे आफ इंडिया के मुताबिक, मंत्री महोदय कहेंगे कि खाली दो हजार मील कम हुआ, मेरे हिसाब से दस पन्द्रह हजार वर्गमील कम हुआ क्योंकि यह एक बात मान लेते हैं कि गोआ और पुन्दूचेरी भारत में आने के पहले से ही उन्होंने गोआ और पुन्दूचेरी के क्षेत्रफल को भारत में गिनना शुरू कर दिया था। कैसे उस बात का विश्वास करें ? आने के पहले ही से गिनना शुरू कर दिया था ? जब आये तब गिनेंगे न ? क्षेत्रफल तो बढ़ाना चाहिये। तो उस बढ़ाव को कम दिखाने के लिए यह मान लेते हैं कि पहले से गिनने लगे थे। असल में कोई चीज बड़ी जबर्दस्त हुई है। वह ऐसे तर्क देते हैं कि पहले अंग्रेज अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते थे। अब हवाई जहाज से सर्वे करते हैं। मैं समझता हूं कि हवाई जहाज से गड्ढों और पहाड़ों का, जमीन की सर्वांगीणता का परिचय मिल सकता है लेकिन हवाई जहाज से जमीन की नाप—यह सिर्फ इन्हीं मंत्रियों के दिमाग की उपज है और तो कहीं ऐसा नहीं होता कि हवाई जहाज से यह होता हो। उस के अलावा कई दफे यह कह दिया करते हैं कि हम अब ज्यादा वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो ज्यादा वैज्ञानिक तरीके के मामले में मैं आपसे एक छोटा सा जिक्र करूंगा कि मैं ने सर्वेयर जनरल को एक खत लिखा था और आप जानते हो मैं अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करता लेकिन यह मामला ऐसा था और क्योंकि खत लिखने का मामला था, फिर भी अपने सिद्धान्तों को तोड़ कर के मैंने सर्वेयर जनरल को खत लिखा 2 जुलाई 1966 को। यह प्रश्न यहां पर आ चुका है मंत्री महोदय को मालूम है। लेकिन अभी तक मुझे कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला है और अब मैं आप से सन्तोष चाहता हूं। जब किसी नौकरशाही को संसद का कोई सदस्य, अपने निजी मामले को छोड़ कर, सार्वजनिक मामलों के बारे में खत लिखे, तो उस का कर्तव्य हो जाता है कि वह उस का जवाब दे और अगर जवाब नहीं देता है तो अपना कर्तव्य बिलकुल निभाता नहीं है। अब यह खत मैं आपको देना चाहता हूं और चाहता हूं कि यह खत आप उसको भेजें और उस से जवाब मांगे। मैं इसे पढ़कर सुनाये देता हूं :

"I will thank you to answer my questions as fully as you can and at your earliest convenience.

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : डाक्टर साहब ने अंग्रेजी में खत लिखा था।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने पहले ही कह दिया है। मैं कभी भी सार्वजनिक जगह पर अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे मौके पर अथवा निजी बातचीत में

[डा० राम मनोहर लोहिया]

कर लेता हूं तो वह भी बुरा काम करता हूं।

"1. What is the total area of India at present or at the last tabulation?

2. What was the total area of India on 15th August, 1947. This must include areas which acceded to and were joined to India later. It must not exclude areas which have been usurped and are now in unlawful possession of foreigners.

3. If there is any difference between 1 and 2, how do you account for it?

4. Is the current survey of India 190 years old? No matter how much survey methods have become more scientific, what is the outside margin of rectification of errors? Do better methods mean anything more than change in the scale of mapping, for instance, from one inch to four miles earlier to two miles and in some cases of detail less now?

5. What is the area of Goa and other Portugese possessions in India and Pondicherry and other French possessions and since when are they being counted with the Indian total?

I have written this letter as part of my parliamentary work and will thank you to give me an early answer. Accept my salutations, Brigadier."

यह खत मैंने ब्रिगेडियर गम्भीर सिंह को लिखा था 2 जुलाई, 1966 को, उस का जवाब मुझ को नहीं आया। अब मैं आपके दरबार में आया हूं और मैं चाहता हूं कि यह खत आप अपनी तरफ से उन को भेजें ताकि आपको पता चल सके और सदन का पता चल सके कि यह मामला कितना गम्भीर है। मंत्रियों के कहने का क्या नतीजा निकलता है, वह मैंने आपको अभी बता दिया है और दरअसल मनसर एक गांव है, मानसरोवर के पास। मैं यह कहना चाहता हूं कि खाली वहां से मालगुजारी मिलती थी, ऐसी ही बात नहीं है, यहां ये उत्तर दे गये कि क्या है, मालगुजारी के कुछ पैसे छूट गये, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि मनसर के लोगों की गणना भारत के लोगों की गणना में होती थी, जनगणना, आदमियों की गणना और वह भी उस गांव की जो मानसरोवर के पास है, 1931 में हुई, शायद 1941 में भी हुई। वहां के अफसरों ने मुझे बताया कि यह मनसर भी हटा दिया गया है, सिक्किम भी हटा दिया गया है, बर्मा सन्धि के कितने हटा दिये गये हैं, मालूम होता है कि इस सरकार ने भारत को एक कुटम्बी सम्पति समझ लिया है, मन में आये जिसको छोड़ दो, दे दो, दे आओ, कोई किसी किस्म की जांच नहीं रह गई है।

अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं रूस और अमरीका—इन दोनों में साझा है, एक तो अच्छा साझा कि दुनिया में युद्ध न होने दो—मैं उसको पसन्द करता हूं, दूसरा साझा कि दुनिया में कोई बड़ी क्रान्ति न होने दो—जिसको मैं बिलकुल नापसन्द करता हूं, कहीं कोई चीज बहुत ज्यादा हिल-हिला जाय, उसको वे सम्भाल नहीं पायेंगे तो रूस और अमरीका वाले दोनों भाईबन्द हो गये हैं क्रांति को रोकने के लिये और युद्ध को रोकने के लिये ऐसी अवस्था में हो सकता है वह जीतें या हारें, लेकिन अगले महीन, दो महीने में एक तरफ पश्चिमी एशिया और दूसरी तरफ भारत-कुछ हो जाय, मामले खटक जाय, तलवार खनक चले, तलवार के बोलने का ढग तो

आप जानते ही हैं, जो कुछ होता है ।

तब मैं आपको एक जगह का नाम सुनाता हूं असम के दोस्त लोग आपको बतायेंगे तनसुखिया से डिगबोई जाते हुए एक शहर आता है उसका नाम है माकूम छोटा गांव या एक छोटा कस्बा उसको समझ लीजिये । मैंने वहां पूछा कि भाई माकूम का मतलब क्या होता है ? तब लोगों ने मुझे बतलाया कि थाईदेश से आक्रमण करने वाले जब यहां आये थे और जब उन्होंने कुछ जमीनें जीत ली थी, तब अपनी भाषा में कहा आओ, बैठो, आपस में बातचीत करें । तब से उस का नाम माकूम पड़ गया है । यह हमारे यहां की पुरानी परम्परा रही है कि कोई विदेशी आता है, हमला करता है, जमीन जीत लेता है और फिर कहता है आओ माकूम, आओ कोलम्बो प्रस्ताव, आओ समझौता और यहां भी बहुत से नादान लोग हैं जो कि ऐसे मौके पर, जब कि हमारी जमीन जीत ली जाती है, तब माकूम करना शुरू कर देते हैं । मैं चाहता हूं कि अगर हमारे ऊपर हमला न हो, जमीन न जाये, तो दुनिया में पूरे फाख्ते की तरह रहना चाहिये-- वह फाख्ता, कबूतर, शान्तिवाला--लेकिन कोई हमारे ऊपर हमला करे, तो उस वक्त तो हमें बाज बनना चाहिये, जब तक बाज नहीं बनेंगे तब तक काम नहीं होगा और इस बार तो जब हमला होगा, चाहे वह सितम्बर में हो, अक्तूबर में हो या नवम्बर में हो, जब कभी भी हो, मैं निश्चित नहीं कहता कि कब हो लेकिन अब की बार हमला हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार तो एक हफ्ते भी ठहरने वाली नहीं है, यह तो चली जायेगी, क्योंकि दोनों के मिले हुए हमले पाकिस्तान और चीन के मिले हुए हमले के सामने इसकी पलटनें पीछे हटेंगी । आप जानते हैं पिछली बार के हमले में एक महीने में एक मंत्री की बली हुई थी और अगर चीन बढ़ता चला जाता तो 15 दिन बाद सरकार की बली हो गई होती । तब डेढ़ महीना लगा था, अब की बार जो अवस्था देश की हो गई है, उस के अनुसार मैं समझता हूं कि एक हफ्ते से ज्यादा इस को आप वक्त मत दीजिये, यह सरकार गिर जायेगी । इस में संकल्प शक्ति नहीं है, यह माकूम सरकार है, इस में मनोबल नहीं है . . .

Mr. Speaker: We have been discussing about border.

डा० राम मनोहर लोहिया : हां, ठीक है, इस में मनोबल नहीं है न । आप जैसे अपनी त्वचा को देखते हैं, वही बात मैं कहना चाहता हूं । जैसी शरीर की त्वचा होती है, वैसी ही देश की सीमा होती है, अगर त्वचा के ऊपर हमला होने के बाद कोई मनुष्य बिलकुल शान्त योगी बन कर बैठा रह जाता है खास तौर से राष्ट्रीय मामलों में सीमा के ऊपर हमला होने पर--मैं जानना चाहता हूं कि अगर डोवर की पहाड़ियों पर हमला हो जाये अगर सिबेरिया के ऊपर हमला हो जाये अगर बेकवान के ऊपर हमला हो जाये तो यहां बहुत से माननीय सज्जन हमारी लोक सभा में हैं जो फौरन दुंदुभि बजाने लग जायेंगे, विश्व युद्ध की बात चिल्लाने लग जायेंगे लेकिन हमारी अपनी खुद की की त्वचा अपने देश की सीमा के बारे में--यह जो मैं सीमा की बात कर रहा हूं और पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं--85 लाख एकड़ जमीन हमारी सर्वे के अनुसार गई है और 5 करोड़ एकड़ जमीन संयुक्त राष्ट्र की किताबों के अनुसार गई है यहां अलग अलग आंकड़े हैं ऐसी सूरत में माननीय अध्यक्ष महोदय इस लोक-सभा के अध्यक्ष के नाते मैं आपसे भी अपील करूंगा कि बहुत संकट का वक्त है, संकल्प शक्ति की जरूरत है, मनोबल की जरूरत है, ऐसे मौके पर कोई

[डा० राम मनोहर लोहिया]

माकूम सरकार न रह पाये हमारा सत्यानाश हो जायगा। माकूम सरकार गिरेगी और उसकी जगह माननीय सदस्यों को अब तैयार रहना चाहिये—एक मनोबल और संकल्प शक्ति की ऐसी सरकार बनाओ जो रक्षा कर सके अपनी सीमा की अपने क्षेत्रफल की अपनी भारतमाता की।

श्री कंवर लाल गुप्त : माकूम नहीं नामाकूल है।

डा० राम मनोहर लोहिया : माकूम भाई भाषा का शब्द है। एक बात भूल गया। एक नक्शा मुझे मिला है सिलहट का जिसमें 12 थाने कब्जे में चले गये हैं पाकिस्तानियों के। तो आप इस को देख लेंगे और अगर ठीक समझें तो आप इस को अपने सदन-पटल* पर रखिये।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी (श्रीनगर) : जनाब सदर मैं महज दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं। इस वक्त ऐवान में बहस हो रही है कि भारत का कुल रकबा कितना है? बहरहाल यह बहुत बड़ी बात है। मैं जानना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर रियासत का रकबा 84 हजार 600 मुरब्बा मील था वह आज रकबा कितना है? आया वह 84 हजार है या 60 हजार है 40 हजार है या जो कुछ भी है वह आज क्या है? जहां तक यह ऐरिया की बात है हमारे पास पूरे फैक्टस एंड फीगर्स होने चाहिएं। इस रियासत जम्मू कश्मीर का ऐरिया कितना है और उस में से ऐरिया कितना गया और वह किस के पास गया है? मैंने श्री कंवर लाल गुप्त और डा० राम मनोहर लोहिया की तकरीरें सुनी। जहां तक रियासत के रकबे का ताल्लुक है यह आज की बात नहीं है। सन 1956 से यह सिलसिला वहां जारी है। सन 1956 में स्टेट गवर्नमेंट ने मरकजी सरकार को बाखबर किया था कि अक्साईचिन के बेश्तर इलाके पर चीन का कब्जा होता जा रहा है और इस सिलसिले में मंसर गांव का भी सवाल आया था। हम बराबर सन 1955 तक वहां से सालाना मालगुजारी वसूल करते थे और 56 के बाद वह मालगुजारी बंद हुई और हम ने उन्हें यह भी बताया कि अक्साई चिन जोकि रियासत का ऐरिया है और सदहा साल से रियासत का एक हिस्सा रह चुका है चीन को उस पर कोई हक नहीं है। अगर हम खुद यह जबान बोले कि चीन कहता है कि हमारा है और हम कहते हैं कि हमारा है तो फिर हम खुद बखुद एक झगड़े को यहां मानते हैं। इस ऐरिया पर झगड़ा है और यह सही मायनों में हमारा ऐरिया नहीं है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अक्साई चिन का सारा ऐरिया जो आज चीन के पास है वह रियासत जम्मू कश्मीर का एक बाजाब्ता हिस्सा है। उस के लिए एक नक्शा आज का नहीं बल्कि गये 100 साल से ज्यादा से हमारे पास मौजूद है और जो 62 में हम ने केन्द्रीय सरकार को दिया जब कि चीन के साथ झगड़ा पैदा हुआ और उस के साथ तमाम डिटेल्स तमाम छोटी छोटी बातें और उस एरिया के चीफटेंस के साथ जो बातचीत व खतोकिताबत हुई वह सब भी हम ने गवर्नमेंट आफ इंडिया को दी। लेकिन आज हमें यह मालूम नहीं है कि जम्मू काश्मीर का एरिया क्या है? अक्साई चिन कोई कहता है 14000 मील है कोई कहता है 1,2000 मील है तो कोई कहता है कि 10,000 मील है। अगर

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the Map was not treated as laid on the Table.

10,000 है तो वह किस एरिया को अपना समझते हैं और किस एरिया को समझते हैं कि वह चीन के हाथ में है। एक तो यह जानकारी जरूरी है। दूसरे यह कि सन् 56 में इत्तिला देने के बाद कि चीन ने उस एरिया में सड़कें बनानी शुरू कर दीं, एरोड्रोम्स बनाने शुरू कर दिये और चीनी फौज की आमदरफ्त शुरू हो गयी जिस से लद्दाख और वह नार्दर्न बौरडर्स हमारे खतरे में पड़ गये। 5-6 साल के बाद जनाब देखेंगे कि चीन ने अचानक हमला कर दिया और कहा कि यह मेरा एरिया है। उस वक्त हम कहते थे कि चीनी हिन्दी भाई भाई हैं। बड़े भाई ने हमला किया तो फिर छोटे भाई को वह सुपुर्द करना ही पड़ा।

आज एक दूसरी बात यहां अर्ज करना चाहता हूं कि दूसरा एक खतरा वहां पैदा हो रहा है। चीन और एक इलाके में दुसाई प्लेस में जो कि बहुत बड़ा मैदान है, सैकड़ों मुरब्बा मील का जो सैंट्रली लोकेटेड है, उस के एक तरफ गिलगित है, एक तरफ स्कर्दू है और एक तरफ कारगिल और लेह है। दुसाई प्लेस कश्मीर वैली के बहुत नजदीक है और दुसाई और उस के दरमियान मुश्किल से 7-8 मिनट का एयर डिस्टेंस होगा।

वहां आज कल चीन गिलगित से स्कर्दू और स्कर्दू से दुसाई प्लेंस तक सड़क बना रहा है और वह एरिया को सन् 1962 के बाद पाकिस्तान ने 3000 के करीब मुरब्बा मील रियासत का एक हिस्सा चीन को दिया था वहां से उस को कनेक्ट कर रहा है और अपनी बहुत बड़ी छावनी वहां बना रहा है। एयरोड्रोम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। यह मैं इतनी इत्तिला देना चाहता हूं और मैं गुजारिश करूंगा मरकजी सरकार से कि सन् 1956 में हम ने इस की इत्तिला दी थी और बाखबर रखा था लेकिन हमारी उस इत्तिला को अहमियत नहीं दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कोई इत्तिला आप को मौजूदा सरकार से इस किस्म की आई है कि गुरेज में क्या हो रहा है। दुसाई प्लेंस में क्या हो रहा है? गुरेज से आगे पैदल जाइये तो यह वहां तक 30-35 मील का फासला है लेकिन अगर हवाई ताकत इस्तेमाल करना हो, हवाई जहाज में जाइये तो एक मिनट लगता है। यह कहीं आपस की गठजोड़ तो नहीं है कि चीन चाहे कुछ करे उस को पूरा हक है कि उसे करे लेकिन मैं सरकार को बतलाना चाहूंगा गुरेज जहां खतरे में पड़ गया वहां सारा देश खतरे में पड़ गया सारा काश्मीर खतरे में पड़ गया। यह अक्साई चिन एरिया से भी ज्यादा खतरनाक एरिया है हालांकि इस वक्त वह एरिया जिस को आजाद कश्मीर आप कहते हैं उस के साथ है लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आजाद काश्मीर के एरिया में और दुसाई प्लेंस में बड़े जोर शोर के साथ आज कल एयरोड्रोम्स का कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है और वहां एरिया भी इतना है कि आप के पालम जैसे 100 एयरोड्रोम्स वहां पर बन सकते हैं। उन के लिए हर एक चीज वहां पर मुहैय्या है। मैं यह चाहता हूं कि आप अब बजाय इस के कि ईस्ट से हमारा कितना एरिया गया, नार्थ से कितना गया, और वैस्ट से कितना गया, वह फैक्ट्स एंड फीगर्स तो उन्हों ने बतला दिये हैं, लेकिन जो अब आप के पास है उस पर तो डैफनिट रहिये और उस को बचाये रखने के लिये पहले से तैयार रहिये। सन् 62 में हमला हुआ, हमले के बाद हम तयारी करने लगें। कहीं फिर ऐसा न हो। मैं कहे देता हूं कि यह जो इन्फारमेशन है आप इस पर दरियाफ्त करा लीजिये कि आया यह वाकयात हैं या नहीं और अगर हों तो इस पर आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दीजिये। बाखबर रहिये और पहले से पूरी तरह तयार रहिये। अपने आप को और सारे देश को खतरे में न डाल दीजिये क्योंकि अबजो चीन है वह करीब करीब रियासत जम्मू काश्मीर के चारों तरफ फैल गया है और अक्साई चिन तो दरकिनार। कहा जाता है कि

[श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी]

बीच में चुमूल है लेकिन चुमूल की भी पोजीशन, मैं उसे कहना नहीं चाहता हूं, शायद मुनासिब भी नहीं होगा हमारे डिफेंस प्वाइंट आफ व्यू से कि हमारी पोजीशन वहां पर क्या है ? दमचुक में हमारी पोजीशन क्या है ? यह मंसिर को जो हमारा गांव है जहां हमारे स्कूल्स थे जहां हमारा सब कुछ था आज वह उन के कब्जे में है । दौलतबेगउल्दी यह हमारा इलाका है लेकिन आज वह उन के हाथ में है । आज वह उन के कब्जे में है । ऐसा न हो कि हम धीरे धीरे चीन के इस खतरे में इतना पड़ जायें कि मुसीबत का हमें एक फौरी तौर पर सामना करना पड़े । यह मेरी गुजारिश है । जो एरिया मैं ने पूछा है वह तो आप बता ही देंगे कि 32 लाख मुरब्बा मील से नीचे वह क्यों आई ? मैं यह भी जानना चाहता कि काश्मीर का जो एरिया पहले 84,600 मुरब्बा मील था वह रकबा अब कितना है ।

मैं बाखबर करना चाहता हूं मरकजी सरकार को और मेम्बरान पार्लियामेंट को कि यह बहुत बड़ा खतरा चीन की तरफ से पैदा हो रहा है । इस के लिये आप आज ही से सोचना शुरू कर दें । कहीं बेखबर तरीके पर हमारे साथ वही न हो जो 1962 में हुआ था ।

شری غلام محمد بخشی : جناب صدر - میں بھی دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا - اس وقت ایوان میں یوں بحث ہو رہی ہے کہ بھارت کا کل رقبہ کتنا ہے - بہر حال یہ بہت بڑی بات ہے - میں جاننا چاہتا ہوں جمو اور کشمیر ریاست کا رقبہ ۸۴ ہزار ۶۰۰ مربع میل تھا وہ آج رقبہ کتنا ہے - آیا وہ ۸۴ ہزار ہے ۔ یا ۶۰۱ ہزار ہے ۳۰ ہزار ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ آج کیا ہے - جہاں تک یہ ایریا کی بات ہے ہمارے پاس پورے فیکٹس اینڈ فیگرس ہونے چاہئیں - اس ریاست جمو کشمیر کا ایریا کتنا ہے اور اس میں سے ایریا کتنا گیا اور وہ کس کے پاس گیا ہے ۔ میں نے شری کنور لال گپتا اور رام منوہر لوہیا کی تقریریں سنیں- جہاں تک ریاست کے رقبے کا تعلق ہے وہ آج کی بات نہیں ہے -

سنہ ۱۹۵۶ سے یہ سلسلہ وہاں جاری ہے - سنہ ۱۹۵۶ میں اسٹیٹ گورنمنٹ نے مرکزی سرکار کو باخبر کیا تھا کہ اکسائی چن کے بیشتر علاقے پر چین کا قبضہ ہونا جا رہا ہے اور اس سلسلہ میں منسٹر کانوں کا بھی سوال آیا تھا - ہم برابر سنہ ۱۹۵۶ تک وہاں سے سالانا مال گذاری وصول کرتے تھے اور ۵۶ کے بعد وہ مال گذاری بند ہوئی اور ہم نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اکسائی چن جو کہ ریاست کا ایریا ہے اور صدہا سال سے ریاست کا ایک حصہ رہا ہو چکا ہے چین کو اس پر کوئی حق نہیں ہے - اگر ہم خود یہ زبان بولیں کہ چین کہتا ہے کہ ہمارا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہے تو پھر ہم خدبخود ایک جھگڑے کو یہاں مانتے ہیں - اس ایریا پر جھگڑا ہے اور یہ صحیح معنوں میں ہمارا ایریا نہیں ہے - میں تو دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور پوری ذمہداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ

اکسائی چن کا سارا ایریا جو آج چین کے پاس ہے وہ ریاست جموں کشمیر کا ایک باضابطہ حصہ ہے - اس کے لئے ایک نقشہ آج کا نہیں بلکہ کئے ۱۰۰ سال سے زیادہ سے ہمارے پاس موجود ہے اور جو ۶۲ میں ہم نے کیندریہ سرکار کو دیا جبکہ چین کے ساتھ جھگڑا پیدا ہوا اور اس کے ساتھ تمام ڈیٹیلس تمام چھوٹی چھوٹی باتیں اور اس ایریا کے چیفٹینس کے ساتھ جو بات چیت جو خطوکتابت ہوئی وہ سب بھی ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کو دی - لیکن آج ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جموں کشمیر کا ایریا کیا ہے - اکسائی چن کوئی کہتا ہے ۱۴۰۰۰ میل ہے کوئی کہتا ہے ۱۲۰۰۰ میل تو کوئی کہتا ہے کہ وہ ۱۰۰۰۰ میل ہے - اگر ۱۰۰۰۰ ہے تو وہ کس ایریا کو سمجھتے ہیں کہ وہ چین کے ہاتھ میں ہے - ایک وہ تو یہ جانکاری ضروری ہے دوسرے یہ سنہ ۵۶ میں اطلاع دیئے کے بعد چین نے اس ایریا میں سڑکیں بنانی شروع کر دیں - ایرو ڈرمس بنانے شروع کر دیے اور چین میں فوج کی آمدورفت شروع ہو گئی جس سے لداخ اور وہ نادرن بارڈرس ہمارے خطرے میں پڑ گئے - ۶-۵ سال کے بعد جناب دیکھیں گے کہ چین نے اچانک حملہ کر دیا اور کہا کہ میرا ایریا ہے - اس وقت ہم کہتے تھے کہ چین ہندی بھائی بھائی ہیں - بڑے بھائی نے حملہ کیا تو پھر چھوٹے بھائی کو وہ سپرد کرنا ہی پڑا -

آج یہ ایک دوسری بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرا ایک خطرہ وہاں پیدا ہو رہا ہے - چین ایک علاقے میں دوسائی پلینس میں جو کہ بہت بڑا میدان ہے - سینکڑوں مربع میل کا جو سینٹرلی لوکیٹڈ ہے اس کے ایک طرف گلگت ہے - ایک طرف اسکردو ہے اور ایک طرف کارگل اور لیہہ ہے - دوسائی پلینس کشمیر ویلی کے بہت نزدیک ہے اور دوسائی اور اس کے درمیان ۰شکل سے ۸یا۸ میلس کا ایر ڈسٹینس ہوگا وہاں آج کل چین گلگت سے اسکردو اور اسکردو سے دوسائی پلینس تک سڑک بنا رہا ہے اور وہ ایریا جو سنہ ۱۹۶۲ کے بعد پاکستان نے ۳۰۰۰ کے قریب مربع میل ریاست کا ایک حصہ چین کو دیا تھا وہاں سے اس کو کیکٹ کر رہا ہے اور اپنی بہت بڑی چھاونی بنا رہا ہے - ایرو ڈرمس انڈر کنسٹرکشن ہیں - یہ میں اتنی اطلاع دینا چاہتا ہوں اور میں گذارش کروں گا کہ مرکزی سرکار سے کہ سنہ ۱۹۵۶ میں ہم نے اس کی اطلاع دی تھی اور با خبر رکھا تھا لیکن ہماری اس اطلاع کو اہمیت نہیں دی گئی - میں چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی اطلاع آپ کو موجودہ سرکار سے اس قسم کی آئی ہے کہ گریز میں کیا ہو رہا ہے - دوسائی پلینس میں کیا ہو رہا ہے - گریز سے آگے

پیدل جائیے تو یہ وہاں تک ۳۰-۳۵ میل کا - فاصلہ ہے لیکن اگر ہوائی طاقت استعمال کرنا ہو - جہاز میں جائیے تو ایک منٹ لگتا ہے - یہ کوئی پس کی کٹھ جوڑ تو نہیں ہے کہ چین چاہے کچھ کرے اس کو پورا حق ہے کہ اسے کرے لیکن میں سرکار کو بتلانا چاہوں گا کریز جہاں خطرہ میں پڑ گیا وہاں سارا دیش خطرہ میں پڑ گیا - سارا کشمیر خطرہ میں پڑ گیا - یہ اکسائی چن ایریا سے بھی زیادہ خطرناک ایریا ہے حالانکہ اس وقت وہ ایریا جس کو آزاد کشمیر آپ کہتے ہیں - اس کے ساتھ ہے لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے - آزاد کشمیر کے ایریا میں دساتی پاہلمس بڑے زور شور کے ساتھ آج کل ایروڈرومس کا کنسٹرکشن وغیرہ ہو رہا ہے وہاں ایریا بھی اتنا ہے کہ آپ کے پالم جیسے ۱۶۰۰ ایروڈرومس وہاں پر بن سکتے ہیں - ان کے لئے ہر ایک چیز وہاں پر پہنچا ہے - میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اب بتائے اس کے کہ ایسٹ سے ہمارا کتنا ایریا گیا نارتھ سے کتنا گیا اور ویسٹ سے کتنا گیا - وہ فیکٹس اینڈ فیگرس تو انہوں نے بتلا دیئے ہیں لیکن جو اب آپ کے پاس ہے اس پر تو ڈیفنس رکھیئے اور اس کو بچانے رکھنے کے لئے پہلے سے تیار رکھیئے - سنہ ۶۲ میں حملہ ہوا حملہ کے بعد ہم تیاری کرنے لگے - کہیں پھر ایسا نہ ہو -

میں کہے دیتا ہوں کہ یہ جو انفارمیشن ہے آپ اس پر دریافت کرا لیجئے کہ آیا یہ واقعات ہیں یا نہیں اور اگر ہیں تو اس پر آج سے ہی ایکشن لینا شروع کر دیجئے - باخبر رہیئے اور پہلے سے پوری طرح تیار رکھیئے - اپنے آپ کو اور سارے دیش کو خطرہ میں نہ ڈال دیجئے کیونکہ اب جو چین ہے وہ قریب قریب ریاست جموں کشمیر کے چاروں طرف پھیل گیا ہے اکسائی چن تو درکنار - کہا جاتا ہے کہ بیچ میں چسول ہے لیکن چسول کی بھی پوزیشن میں اسے کہنا نہیں چاہتا ہوں شاید مناسب بھی نہیں ہوگا ہمارے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہماری پوزیشن وہاں پر کیا ہے - دمچیکہ میں ہماری پوزیشن کیا ہے - یہ منسٹر جو ہمارا گاؤں ہے جہاں ہمارے اسکولس ہے جہاں ہمارا سب کچھ تھا آج وہ ان کے قبضہ میں ہے - دولت بیگ اولدی یہ ہمارا علاقہ ہے لیکن آج وہ ان کے ہاتھ میں ہے - آج وہ ان کے قبضہ میں ہے - ایسا نہ ہو کہ ہم دھیرے دھیرے چین کے اس خطرہ میں اتنا پڑ جائیں کہ مصیبت کا ہمیں ایک فوری طور پر سامنا کرنا پڑے -

یہ میری گزارش ہے - جو ایریا میں نے پوچھا ہے وہ تو آپ بتا دیںگے؟ ہی کہ ۳۲ لاکھ مربع میل سے نیچے وہ کیوں آئی - میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا جو ایریا ۸۴۶۰۰ مربع میل کا تھا وہ رقبہ اب کتنا ہے -

میں باخبر کرنا چاہتا ہوں مرکزی سرکار کو اور ممبران پارلیامنٹ کو کہ یہ بہت بڑا خطرہ چین کی طرف سے پیدا ہو رہا ہے - اس کے لئے آپ آج ہی سے سوچنا شروع کر دیں - کہیں بے خبر طریقے پر ہمارے ساتھ وہی نہ ہو جو ۱۹۶۲ میں ہوا تھا -]

18 hrs.

Mr. Speaker: Shri Ranga. There are a number of names before me. If all parties and groups are to be represented, it will take till 8 P.M. Yesterday also, we carried on till about 8 P.M. when there was no quorum and the House had to be adjourned without hearing the Minister's reply. I do not think this is a subject where it is necessary that every group and party should be represented. I leave it to your judgment. If we continue as we did yesterday and the Minister is not in a position to reply, what for are we holding the discussion, for whose benefit? So let us fix up a time-limit. This discussion is scheduled from 5 to 6. We will have another half an hour in which I will allow Shri Ranga and one or two others and then the Minister could reply.

श्री रबी राय (पुरी) : क्या प्राज भी प्रधान मंत्री उपस्थित नहीं रहेंगी? यहां पर इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार हो रहा है।

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, अपोजीशन वालों को 6 बजे तक बोलने का मौका मिला है हम को भी उसी के मुताबिक मिलना चाहिये।

Mr. Speaker: He can come and sit in this Chair and continue for one hour. I have no objection.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : हमें प्राधा टाइम दे दिया जाये। हम प्रौर कुछ नहीं चाहते।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि.......

Mr. Speaker: I have called Shri Ranga because he may be able to give some information which Shri Sheo Narain will not be able to give. If Shri Sheo Narain can give some information or throw some new light on the border situation and all that, here and now I am prepared to give him a chance. What is the use of shouting?

श्री शिव नारायण : मैं चांस नहीं मांग रहा हूं। प्राप ने कहा कि 6 बजे तक का टाइम था। मैं कहना चाहता हूं कि प्राप ने श्री रंगा को बुलाया है। उन के बोलने के बाद प्राप मिनिस्टर साहब को बुला लीजिए।

Mr. Speaker: It is a very good suggestion. I am glad he has made it. If the House accepts it, after Shri Ranga has finished, I have no objection to acting upon it.

Shri Ranga (Srikakulam): At the outset, I would like to express my gratitude to the friends who have given notice of this discussion and also to the friends who have taken part in this debate. The least that any civilised government, sensible government,

[Shri Ranga]

can be expected to do is to protect the territorial integrity of the country. That is exactly where along with our friends who have spoken, I also wish to charge this Government with having failed to do. We do not want to steal or conquer the land of any other country, but we would not like to allow other countries who are our neighbours to encroach upon ours.

Aksai Chin has been referred to. When it was being occupied, when that road was being laid, when the whole of that territory was parcelled out and taken out of our control, the country was kept completely in ignorance. It needed any amount of prodding repeatedly by a number of members in this House in those days before we could get the Government of those days to admit that it had happened. Only the other day, my hon. friend, said that Latitilla-Dumbari really belonged to us and yet it came to be occupied by Pakistan. Until his attention was drawn, he would not come out openly and say that this had happened.

Secondly, any moment any little encroachment is made on any part of our country, whoever happens to be responsible for that part of the national duty should hasten to come to this House and say that such and such things are happening. We may be the weakest possible people, yet we need not recognise such illegal encroachments. What is more, it is the duty of the Minister, in those days the king, to take the people into his confidence and then say this is what has happened, we are weak, nevertheless we continue to protest. That is how Chiang Kai-shek had laid claims to huge areas of our country, NEFA as well as northeast area. Now, his successors, the communists in China, have been taking advantage of the claims that he had made, the maps that he had published, against which the later Swaraj Government was pussilanimously silent and was unable to say anything except make a mention when they were having their own dinners and drinks here in Delhi, when the *Hindi Chini bhai bhai* was going on, our Prime Minister simply, quietly making mention to Chou En-lai and Chou En-lai smiling, and our Prime Minister accepting it as satisfaction.

18.07 hrs.

[SHRI G. S. DHILLON *in the Chair*]

All those things happened. I do not wish to go into all those details. Our friends have given all the useful details here.

A very useful, constructive suggestion has come from my hon. friend Mr. Gupta that there should be committee of Members of Parliament. A permanent committee it should be. From time to time you may change its Membership, but the committee must be there. Whenever the house is not in session, any moment any such untoward thing happens I would charge the Government with the primary task of taking that committee into confidence and telling them what is happening, what encroachments are being made.

What is the use, somebody might say, of the Spanish people protesting against the British occupation of Gibralter. They had gone on for centuries, but today it has become a live issue between the British and the Spanish people. Similarly, we need not accept their claims, their illegal occupation. We may not be in a position to drive them out of Aksai Chin for instance and other areas, so far as the Chinese are concerned. Yet, our claim would be there that the Chinese are there in an illegal fashion; if and when we get an opportunity we would certainly see that they vacate these lands.

One of the greatest tragedies that has taken place in this part of the world, and especially to India, was that unholy acceptance of China's claims over Tibet. If it had not been done, our position would have been

entirely different. Now, we should right that position.How can we do it? We may not be able now to match with our arms and armies and liberate Tibet and thus assure ourselves of a very good and peaceful neighbour, but We can at least do one thing, we can recognise the Dalai Lama as the head of the Government that we recognise, that we are prepared to recognise. There is no sense at all; there is no sacredness about the earlier agreement that we had reached. That agreement had lasted too long and wrongly too. We should never have gone into it. It is high time we simply dismissed it. My hon. friend says: how can we? When we are thinking of getting rid of these covenants that you have reached with your own princes here in this country, is it too much for us to expect the Government to denounce that unholy agreement that we had reached because of our ignorance of our own duties towards our country.

All that I have to ask now is this. The people in this country would never excuse this Government so long as it continues to recognise the Chinese occupation and Chinese claims over this Manasarovar. It is a part, very heart of our country, of our tradition, of our lore and literature. From Kalidasa and far beyond to the very earliest times down to this day, Manasarovar is part of us, is a part of our country. That is only a symbolic claim that I am making. All the rest of it has been mentioned by our friend Bakshi Gulam Mohammad. I welcome his intervention in this debate today. All these will have to be looked after by this government and my fear is that the secretariat is not properly attuned to the nationalistic feelings and urges and demands of our people and for the proper and full protection of the territorial integrity of our country. I hope my hon. friends who are today in charge of this government would begin to think and discharge their minimum responsibility and minimum duty of protecting the territorial integrity.

सभापति महोदय, श्री प्रेम चन्द वर्मा ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : स्पीकर साहब ने कहा था कि इनके बाद मिनिस्टर बोलेंगे ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : स्पीकर साहब कह गए हैं कि मिनिस्टर साहब बोलेंगे । अगर आप उनको मौका देते हैं तो आपको हम सब को देना होगा ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मिनिस्टर साहब को बुलाना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है । मैं बैठ जाता हूं ।

श्री रणबीर सिंह : मैं दो तीन मिनट जरूर बोलना चाहूंगा । मैंने लिख कर भी दिया है । आप उधर वालों को बुलाते जाते हैं, इधर वालों को नहीं बुलाते हैं । हम सारे क्या भटूटू बैठे हैं ?

श्री कंवर लाल गुप्त : जो स्टेटमैंट मिनिस्टर साहब ने दी है उस में यह नहीं बताया है कि कब कब टरिटरी पाकिस्तान और चीन के पास गई है । अब आप बतायें कि किन हालात में यह उनके कब्जे में गई है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कब इसके बारे में आपने लोक सभा को खबर दी । इन दो चीजों को आप एवायड न करें । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आप हाउस की कमेटी बिठाने के लिए तैयार हैं ?

सभापति महोदय: मैं दो मिनट लिमये साहब को दे सकता हूं ।

श्री मधु लिमये : दो तीन मिनट में मेरा काम नहीं चल सकता है । अभी बोलने का अवसर आप न दें, मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन मेरा व्यान अलग से आना चाहिये । 115 अध्यक्षीय निर्देश के मातहत मंत्री महोदय ने जो गलत व्यानी की है

[श्री मधु लिमये]

लाठी टोला और डूमा बाड़ी के बारे में 17 जुलाई को, उसके बारे में मेरा व्यान है।

श्री रणधीर सिंह : क्या बीच में ले आए हैं?

श्री मधु लिमये: मैं दो तीन मिनट में खत्म नहीं कर सकता हूं। पहले का मेरा नोटिस है, उनके अनुसार इसको रखिये।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : अगर आप दूसरों को बुलाते हैं तो मेरा नम्बर पहला है। चागला साहब को अगर आप बुलाते हैं तब मैं नहीं बोलूंग। लेकिन अगर आप दूसरों को बुलाते तो मैं बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय : आपने खुद कहा है कि चागला साहब बोलें मैं नहीं बोलूंगा। मुझे पता नहीं कि स्पीकर साहब ने मधु लिमये साहब के लिए क्या एग्रो किया था।

लेकिन अब मैं चागला साहब को बुलाता हूं।

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): Mr. Chairman, Sir, the area of India is the area as defined in the Constitution and the computation of that area must be according to the constituent units laid down in the Constitution. Whatever the figures may be, however much they may vary, the process of computation must include every inch of our country. I want to assure the House, whatever may be the discrepancies in the figures—I will give explanations for it presently—our attempt has been through the Survey of India and other agencies to see that every inch of our country is properly computed. Computation cannot change the area of a country. Every inch of our country is sacred. We realise it. We have also taken the oath of loyalty to the Constitution. I agree with Mr. Ranga that the first primary, elementary duty of every Government is to protect the security and integrity of the country. Therefore, I do request Dr. Lohia not to go by figures. I will explain why the discrepancies have arisen, but if he concludes that we have given away our territory, then we are guilty not only at the bar of Parliament but at the bar of the country. I will explain why discrepancies have occurred here and in UN.

Shri Kanwar Lal Gupta: What is the total area now?

Shri M. C. Chagla: I will come to that. First of all, although Dr. Lohia may say it is not a fact, the Survey of India tells me—as Minister of Education, the Survey of India was under me—that as years go on, the method of survey is improving. Dr. Lohia says, it only affects the scale of the map. It is not so. Today through aerial survey and other instruments that we possess, we can compute the area of India much more satisfactorily.

श्री मधु लिमये : तभी वह घट रहा है।

श्री म० क० चागला : इसीलिए नहीं घट रहा है। घटता भी है जब गलती होती है। लेकिन बात यह है कि जो फर्क हुआ है उसका सबब यह है कि आज हमारे पास अच्छे हथियार हैं जिन की मदद से हम बेहतर तौर पर गिन सकते हैं कि क्या हिन्दुस्तान का एरिया है।

डा० राम मनोहर लोहिया : सिक्किम वाला गिन रहे हो आजकल या नहीं? बर्मा को कुछ दिया है या नहीं? लांगजू सी मील है या एक मील? सब चीजों का जवाब दो।

Shri M. C. Chagla: It is not only in India that these differences occur. I will give the variations of figures of selected countries. In India, as my statement shows, the variation is 561 miles. The percentage comes to 0.04. In Australia, the variation is 0.11 per cent. In Argentina, there is a decrease and the percentage is 1.5. In Iran there is an increase, but there is variation.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप मुझे मजबूर करते हैं कि मैं आपको टोकूं । मेरे पास भी यहां है अमरीका का रूस का । मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि अमरीका का 1950 से लेकर 1958 तक बिल्कुल एक सा रहा है और फिर 78 लाख किलोमीटर से बढ़कर 93 लाख किलोमिटर हो गया है क्योंकि उस में हवाई शामिल हो गया । उसी तरह से रूस का है । वह बढ़ा है । जब कोई न कोई नया इलाका आ जाता है तो वह बढ़ जाता है । घटना हुआ तो है ही नहीं सिवाय आस्ट्रेलिया के जिस के कुछ द्वीप यानी आइलैंडज यानी जजीरे चले गए हैं । मेहरबानी करके आप इसके ऊपर ध्यान दें ।

Shri S. Kundu: Between 1953 and 1954, during the period of about 10/11 years, we have lost about 8,000 square miles of our area which comes to 900 square miles per year. Would you kindly say specifically whether in the coming years, we are going to lose at the same rate?

Shri M. C. Chagla: I will point out the position with regard to China. If my hon. friends interrupt me, I cannot finish my speech. Then, the other reason is this. We have surveys taken by the States. They are taken only for the purpose of revenue, not for the purpose for which the Survey of India undertakes survey. Very often, because the Survey of India figures were not ready the figures given by the States have been supplied to the United Nations for its demography The third is the question of census. Figures of a year are taken for the purpose of census. The United Nations ask us to give the figures for demographic year book. We supply the census figures. Sometimes when the census is not held or completed in certain parts of the country, we tell them that we can only give them provisional figures because the census has not been completed and we have not got the total figures.

डा० राम मनोहर लोहिया : ऐसा नहीं करना चाहिए था । उसी में आप ने मौका दे दिया कि वह जम्मू ऐंड काश्मीर को निकाल दें । सन 61 में यह किया ।

श्री मु० क० चागला : ऐसा नहीं हुआ हमने लिखा था यूनाइटेड नेशंस को कि यह प्राविजनल है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप ने क्यों भेजा उन को मौका मिल गया चागला साहब । अगर मान लीजिए 61 में न भेजते तो उन को मौका न मिलता ।

Shri M. C. Chagla: Other considerations are also there which I want to point out.

डा० राम मनोहर लोहिया : अच्छा मैं यह सदन पटल *पर रखना चाहता हूं रूस अमेरिका वगैरह के ।

श्री मुत्थाल राव : आप ने स्पीकर साहब को भेजने के लिए कहा था ...

Mr. Chairman: The hon. Member cannot speak directly like this.

Shri Muthyal Rao: I am speaking through you only.

Shri M. C. Chagla: The other difficulty has arisen....

Mr. Chairman: I realise that hon. Members are naturally perturbed over the whole affair.

Shri M. C. Chagla: So am I. We all feel anxious about the integrity of our country. I quite appreciate the anxiety of the House and I fully share it. I am satisfied, and I hope to satisfy the House, that this Government has not given away one inch of the

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the statement showing the total area of certain countries as appeared in the U.N. Year Books from 1950 to 1964, was not treated as laid on the Table.

[Shri M. C. Chagla]

country or conceded that a single inch of the territory of this country as defined in the Constitution is not part of our country.

Difficulties have also arisen for this. Take Jammu and Kashmir. Up to 1960 the United Nations included Jammu and Kashmir in the figure as our area and from 1960 suddenly they dropped it out. We have protested all the time. We have written to the United Nations that Jammu and Kashmir is an integral part of India and they were wrong in excluding it. Well, our protests have so far not been listened to.

श्री कंवर लाल गुप्त : आप ने अपने स्टेटमेंट में आजाद काश्मीर नहीं रखा जो स्टेटमेंट मेरे सवाल के जवाब में दिया ।

श्री मु० क० चागला : नहीं, वह है । यह बात दुरुस्त नहीं है । इस स्टेटमेंट में सारा काश्मीर है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : जो स्टेटमेंट 31 जुलाई को आया मेरे सवाल के जवाब में उस में नहीं है आजाद काश्मीर का ।

श्री मु० क० चागला : मैं काश्मीर के बारे में बाद में बात करूंगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : तो अब नहीं उस को शामिल करते हैं ? वह पहले किया करते थे ?

श्री मु० क० चागला : जी हां ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अच्छा एक बात चलो मालूम हुई । ऐसे ही बताते चलिए क्या क्या नहीं करते हैं ।

Shri M. C. Chagla: The other difficulty is this. Sometimes Sikkim has been included, sometimes Sikkim has not been included. I do not agree with my hon. friend, Dr. Lohia, that in the area of India we should include Sikkim because our Constitution does not say that Sikkim is part of India.

डा० राम मनोहर लोहिया : अच्छा लांगजू गिनते हैं कि नहीं चागला साहब ? बड़ी मेहरबानी होगी बड़ी दया करेंगे, सिर्फ लांगजू का बता दें ।

Shri M. C. Chagla: Then difficulty has arisen because Goa and the French possessions here were not included, or included before we got juridical possession from France. Today the picture is clear. The whole of Jammu and Kashmir—there is no doubt about that—belongs to India, the Portugese possessions belong to India. Since 1953 sometimes they were included, sometimes not included because the picture was not clear. Goa was not taken possession of by us, and also jurisdical possession of Pondicherry and other French possessions had not come to us.

Now I come to Jammu and Kashmir. My friend, Shri Bakshi is not here.

एक माननीय सदस्य : बख्शी साहब मौजूद हैं ।

Shri M. C. Chagla: Let me come to the question of Kashmir. He wanted to know what the area of Jammu and Kashmir was. I have got the exact figures, which I will give him, which includes that part of Kashmir which is under the illegal occupation of Pakistan. The area is 86,023 sq. miles. . .

श्री मधु लिमये : इस में मनसर भी गिनते हैं ? . . . . . (व्य ध न) . . . अरे जब मैंने मनसर आप को बताया था तब तो आप ने चीन को खत लिखा था ।

Shri M. C. Chagla: As regards Jammu and Kashmir, may I point out that the total area illegally occupied by Pakistan since Pakistan's aggression in Jammu and Kashmir in 1947 is approximately 32,500 sq. miles.

Shri Kanwar Lal Gupta: What do you mean by approximately? You should be definite.

Shri M C. Chagla: We cannot go and take a survey of a territory which is in illegal occupation. We can have only an approximate figure Out of this, a little over 2,000 sq. miles of territory has been illegally ceded by Pakistan to China under the so-called Sino-Pakistan border agreement. This is the position with regard to Kashmir. I have given the total area, which includes that portion of Kashmir which is ours but which is illegally occupied by Pakistan,—the area there has to be approximate —and I have given the area which Pakistan has again illegally given over to China.

I must also give the figures as regards the territory which is in illegal possession by China. The figures are these. Approximately 14,500 sq. miles is our territory in possession of China.

As regards Pakistan, let me make this position clear. There are areas about which there is no dispute and where the border has been demarcated, but these remain in adverse possession of Pakistan pending return to India after final demarcation of the border has been completed. I have got the names of the areas. Therefore, when the border is finally demarcated—we are also in possession of some areas which really belong to Pakistan. It is a matter of exchange —when the border is finally demarcated, these will be exchanged; there is no dispute between us and Pakistan as to the ownership or the title of these areas.

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : कितना उन के कब्जे में है कितना आप के कब्जे में है ? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।

Shri M. C. Chagla: Then, there is the second category—the disputed areas which belong to us but on which Pakistan is laying claim and is in possession of Pakistan. Therefore, there are certain areas which we claim as ours and which are in illegal possession of Pakistan. We have not conceded the right of Pakistan to be in possession of these villages. The names of the villages can be mentioned. I have made it quite clear that Pakistan was in temporary possession of these because of the ground rules and the settlement arrived at between the army officers.

Shri Kanwar Lal Gupta: Why do you make settlement without prior approval of Parliament? That is our question.

Shri M. C. Chagla: I will come to that. We have not accepted the juridical title of Pakistan to these areas.

Shri Kanwar Lal Gupta: But why did you give them possession?

Shri M. C. Chagla: We have not given them possession. It is adverse possession. We have still to demarcate and determine the boundary in this area where there is dispute. If Government have conceded to Pakistan those areas as theirs, then certainly it will be our duty to come and tell Parliament of it. But here it is a temporary phase. We have not accepted the Position.

Shri Ranga: We have become paralysed.

Shri Kanwar Lal Gupta: You have given possession to them and then you say that you do not concede them the right.

Shri M. C. Chagla: I have explained it in detail.

श्री कंवर लाल गुप्त : पाकिस्तान का कितना एरिया पजेशन में आप ने लिया है ? पाकिस्तान ने एक इंच भी जमीन आप को इस तरह से दी कि रहेगा पाकिस्तान का लेकिन पजेशन आप लीजिए ?

Shri M. C. Chagla: This is the position.

Shri Kanwar Lal Gupta: You have not informed Lok Sabha anything.

[Shri Kanwarlal Gupta]

You did not say anything about it; not even a word about it.

Shri M. C. Chagla: This is the position about Kashmir, China and Pakistan.

डा० राम मनोहर लोहिया : बर्मा को कितनी जमीन दी ?

श्री मु० क० चागला : कुछ नहीं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : देखिए, संभल कर बोलिएगा, फिर कहीं फंस न जाइएगा ।

श्री मु० क० चागला : मुझे मालूम है कि आप प्रिविलेज मोशन का डर बता रहे हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : हां, संभल कर बोलिएगा ।

Shri M. C. Chagla: I made a statement when we entered into a boundary agreement, and I told the House that we have not given Burma a single inch of our territory. Burma has never claimed a single inch of our territory. I will be fair to Burma.... (*Interruption*).

My hon. friend, Dr. Lohia, referred to the letter to the Surveyor General. That particular Surveyor General resigned soon after the letter was written. That is the only explanation I can think of why a reply was not sent.

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति महोदया मेरे सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया गया, इस डिबेट का क्या फायदा है । वे तो एरिया की बात कर के क्लोज करना चाहते हैं, जब कि हम ने यह पूछा था कि आपने लोक सभा को जो 1956, 1962 1964 और 1961 की सूची दी है, जो भूमि पाकिस्तान के कब्जे में आजादी के बाद गई है उसकी सूचना आपने लोक सभा को कब दी और वह पाकिस्तान के पजैशन में क्यों जाने दी ?

Shri M. C. Chagla: I am glad that my hon. friend, Shri Gupta, accepts the unfortunate fact in our political life, however deplorable it may be, that China and Pakistan should be in possession of our territory, that today we are not in a position to take it back; therefore, he suggested a political and diplomatic way of recovering this.

With regard to China, we accepted the Colombo proposal. We are willing today to discuss it with China on the basis of the Colombo proposals. China never accepted the Colombo proposals. We even suggested going to the International Court of Justice or to international arbitration. China did not accept it. Therefore our only hope is that some time soon a dialogue will start between us and China, that China will see reason and that some settlement will emerge after that. Even my hon. friend, Shri Gupta, concedes that it is unfortunate that we are not in a position today, apart from the fact that it is against our principles, to mount a military invasion to recover these territories.

डा० राम मनोहर लोहिया : उन को जमीन देते रहो और फिर बात करते रहो ।

Shri M. C. Chagla: I have nothing more to add.

डा० राम मनोहर लोहिया : ठीक है मालूम करो ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरी रिपीटेड रिक्वैस्ट के बाद भी मिनिस्टर साहब उस को टालना चाहते हैं । इन्होंने देश के साथ फौड किया है, इस लोक सभा के साथ धोखा किया है .....

डा० राम सुभग सिंह : इस में फौड और धोखे की क्या बात है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं डा० राम सुभाग सिंह से प्रार्थना करूंगा कि यह कोई मेरी पार्टी का सवाल नहीं है, यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है । लोक सभा को कान्फीडेन्स में लेना चाहिये, आपको बताना चाहिये कि ये हिस्से पाकिस्तान में कब गये, किन हालत में गये । मैंने पत्र लिखा था, आपने कल जवाब दिया है कि लोक सभा में आपको

[श्री कंवर लाल गुप्त]

बताया जायगा कि किन हालात में ये पाकिस्तान में गये और कब कब हम ने जवाब दिया। यह चीज ठीक नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, यह देश के साथ फ्राड की बात है।

Shri M. C. Chagla: If any incorrect statement is made by a Minister the Rules lay down a specific procedure. Today we are here discussing a motion under rule 193. The motion says:—

> "to raise a discussion on illegal occupation of Indian territory by China, Pakistan and other countries"

and I have come to answer it. I have explained to what extent Pakistan and China are in illegal possession of our territory. I have given the specific area and the specific places. I cannot do anything more.

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। मेरे पास छागला साहब का जवाब है।

Mr. Chairman: Please sit down. I am on my legs. I think, the Minister has tried his best to answer the points. He even yielded and patiently heard some of the interruptions. He tried to satisfy the House to the extent he could under this rule. How, there will be no further question.

Shri Ghulam Mohammad Bakshi: Just for my information . . .

Mr. Chairman: Are you prepared to answer Shri Bakshi?

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस तरीके से तो यह पार्लियामेन्ट्री सिस्टम बिगड़ जायगा। इन को कहिये कि इस तरह से न करें, तैयारी कर के सारी सूचना लायें।

Mr. Chairman: That is a different thing. I think, the Minister has said...

Shri Kanwar Lal Gupta: You do not comment on that. He is a miserable failure in this.

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : मैं निहायत अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि छियासी हजार और कुछ मुरब्बा मील काश्मीर का रकबा आपने बताया है। यह टोटल रकबा है, जिसे रियासतें-जम्मू व काश्मीर कहते हैं। उस में से 32 हजार मुरब्बा मील आजाद काश्मीर के पास हैं और 14 हजार मुरब्बा मील चीन के पास है, उस का मतलब हुआ कि 40 हजार मुरब्बा मील हमारे पास है या शायद कुछ इस से कम हो—क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मैं हिसाब में हमेशा फैल होता था, इसी लिये पूछता हूं कि क्या 14 हजार मुरब्बा मील चीन के पास है, 32 हजार मुरब्बा मील आजाद काश्मीर के पास है और जो हमारे पास है, वह सिर्फ 40 हजार मुरब्बा मील है ?

Shri M. C. Chagla: Yes, that is arithmetic.

श्री जी० भ० कृपालानी (गुना) : मैं यह कहता हूं कि ख्यामख्वाह झगड़ा कर रहे हैं। एक हमारे बड़े सीधे सन्त थे—श्री रामकृष्ण परामहंस। वह कहते थे कि कई दफ़ा परमेश्वर को हंसी आती है .....

Mr. Chairman: Do you want to answer the first question?

श्री जी० भ० कृपालानी : मैं तो एक मिनट लूंगा। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते थे कि परमेश्वर को हंसी आती है जब दो आदमी हाथ में फीता लेकर जमीन मांप करते हैं और कहते हैं कि यह जमीन तुम्हारी है और यह जमीन हमारी है। परमेश्वर कहता है कि यह जमीन तो सब हमारी है। हमारी सरकार की भी यही हालत है, वह यह समझती कि यह सब जमीन परमेश्वर की है।

Mr. Chairman: The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m.

18.37 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 9, 1967/Sravana 18, 1889 (Saka).

GMGIPND—L.S. II—1884(ai) LSD—3-6-68—1010.